



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]
No. 148]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2006/आषाढ़ 13, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2006/ASADHA 13, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2006

(निर्णायक मध्यावधि समीक्षा)

विषय:- थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयात के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/13/2006-डीजीएडी - जबकि 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 06/08/2002 की अधिसूचना सं. 26/1/2001-डीजीएडी के अनुसार थाईलैंड, अमरीका और कोरिया गणराज्य (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक

फाइबर (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया था। दिनांक 13/9/1996 की मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी और दिनांक 14/10/1997 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 47/एडीडी/आईडब्ल्यू के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 26/4/1998 को अधिसूचना संख्या 21/1/99-डीजीएडी के द्वारा मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई थी और दिनांक 19/4/2000 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 21/1/99-डीजीएडी के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। दिनांक 7/8/2001 की अधिसूचना सं. 26/1/2001-डीजीएडी के द्वारा पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की गई थी और दिनांक 6/8/2002 की अधिसूचना सं. 26/1/2002-सीमाशुल्क के द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे।

और जबकि दिनांक 9/10/2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 106/2002-सीमाशुल्क के अनुसार संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच और इस वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर, एक्राइलोनाइट्राइल, जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन हेतु एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, के कम से कम 85% भार वाली सिंथेटिक पॉलिमर की एक लंबी श्रृंखला है। प्रमुखतः इसका विवरण फाइबर के रंग, लम्बाई और डेनियर के संदर्भ में दिया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र, घरेलू सामग्रियों के विनिर्माण के लिए किया जाता है और उद्योगों इत्यादि में भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। इसको सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त इसको सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची -1 के शीर्ष 550330 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 55033000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और उसमें निहित पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जानी अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का मानना है कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995, यथा संशोधित की धारा 9क(5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार इस स्तर पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित होगा। उपर्युक्त प्रावधान के संदर्भ में, संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों में से एक मै0 थाई एक्रिलिक फाइबर कम्पनी लि0 थाईलैंड ने थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता का प्रमाण देते हुए एक याचिका दायर की है।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश थाईलैंड है।

5. समीक्षा का आधार

याचिकाकर्ता का दावा है कि पाटन एवं क्षति दोनों की स्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है जिसके कारण लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना आवश्यक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा में दिनांक 6/8/2002 के अपने अंतिम जांच परिणाम के द्वारा थाईलैंड से एक्रिलिक फाइबर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी और तत्पश्चात् इन शुल्कों को दिनांक 9/10/2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 106/2002-सीमाशुल्क के अनुसार अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता पर 0.16 अम.डा./किग्रा. के दर से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वर्तमान शुल्क के लागू होने के पश्चात् 3½ वर्ष की अवधि बीत चुकी है और निर्णायक समीक्षा में 12.39% के रूप में निर्धारित पाटन मार्जिन में संबद्ध वस्तुओं की बाजार स्थितियों, लागतों और कीमतों में काफी परिवर्तन हो चुके हैं। याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया पाटन मार्जिन के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और दावा किया है कि उनमें काफी गिरावट आई है, जिसके कारण अब वर्तमान शुल्क को समाप्त किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं कर रहे हैं। अतः याचिकाकर्ता ने थाईलैंड के मूल के और/अथवा याचिकाकर्ता द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने की आवश्यकता के संबंध में अनुरोध किया है, चूंकि घरेलू उद्योग की किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है।

6. प्रक्रिया

याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बदली हुई परिस्थितियों को इंगित करते हुए लागू उपायों की समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 6/8/2002 को सं. 26/1/2001-डीजीएडी के अनुसार अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम समीक्षा और दिनांक 9/10/2002 की अधिसूचना द्वारा लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा, उपर्युक्त नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के प्रावधानों के संदर्भ में बदली हुई परिस्थिति के मद्देनजर उचित है। इस समीक्षा के दिनांक 6/8/2002 की अधिसूचना सं. 26/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

7. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 (12 महीने) है। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 और अप्रैल 2005 - मार्च, 2006 शामिल होंगे।

8. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, उनके दूतावासों/भारत में उनके उच्चायोगों/प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में उसके ज्ञात संबद्ध आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को संबंधित संगत सूचना, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

कक्ष सं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली - 110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

9. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में दिया जाए जो उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है और प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd July, 2006
(Mid-term Review)

Subject: Initiation of Mid-term Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Thailand.

No. 15/13/2006-DGAD - Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), vide Notification Number 26/1/2001-DGAD dated 06.8.2002, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Thailand, USA and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries). The original anti dumping investigation was initiated on 13.9.1996 and definitive anti dumping duty was recommended vide final findings Notification No. 47/ADD/IW, dated 14.10.1997. Subsequently mid-term review was undertaken vide Notification No. 21/1/99-DGAD, dated 26.4.1999 and definitive anti dumping duty was recommended vide final findings Notification No. 21/1/99-DGAD, dated 19.4.2000. Sunset review of the anti dumping duty was initiated vide Notification No. 26/1/2001-DGAD, dated 07.8.2001 and the final findings were issued vide Notification No. 26/1/2001-DGAD, dated 06.8.2002.

And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 106/2002-Customs, dated 09.10.2002.

2. Product Under Consideration

The product involved in the original investigation and this current review is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 85% by weight of Acrylonitrile which is the major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and

denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items and it has a great industrial use etc. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified under the heading 550330 of schedule-I of Custom Tariff Act and 55033000 as per Indian Trade Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. The Designated Authority considers that the mid term review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of rule 23 of AD Rules and section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended. In terms of the above provision one of the exporters, M/s.Thai Acrylic Fibre Company Ltd., Thailand of the subject goods, have filed an application substantiating the need for mid term review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Thailand.

4. Countries Involved:

The country involved in the present investigation is Thailand.

5. Grounds for Review

The applicant has claimed that the conditions of dumping have changed substantially requiring a review of the anti-dumping measure in force. The Designated Authority had recommended anti dumping duty on imports of Acrylic Fibre from Thailand vide its final finding dated 6.8.2002 in the sunset review and the duties were subsequently notified vide custom notification No. 106/2002-Customs, dated 9.10.2002. The applicant is subjected to anti dumping duty @US\$ 0.16/Kg. The applicant has claimed that a period of 3 ½ years has already been lapsed since the imposition of existing duty and the dumping margin determined in the sunset review as 12.39% had undergone significant changes due to change in market conditions, cost and prices of subject goods. The applicant has prima facie filed the positive evidence regarding the dumping margin and claimed that it has come down significantly warranting removal of existing duty.

The applicant has claimed that they are not dumping the subject goods in India. Therefore, the applicant has requested for the need for mid term review of the

anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in Thailand and/or exported by the applicant, as the domestic industry is not suffering any injury.

6. **Procedure:**

Having regard to the information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the final findings notified vide No. 26/1/2001-DGAD dated 06.8.2002 and the definitive anti dumping duty imposed by Notification dated 09.10.2002 is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra. The review covers all aspects of Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 06.8.2002.

7. **Period of Investigation:**

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2005 to 31st March 2006 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 and April 2005-March 2006.

8. **Submission of Information:**

The exporters in subject countries, their government through their Embassies/High Commissions in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. **Time Limit:**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned

above not later than forty days (40 Days) from the date of letter of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. **Inspection of Public File:**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority